

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'ज्ञान भारतम् मिशन' के अंतर्गत राज्य के शीर्ष - 3 ज़िले
2.	राजस्थान का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र : ताला (कुंडा की ढाणी)
3.	देश का पहला ज़िंक पार्क - खानखला (भीलवाड़ा)
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) का राजस्थान चैप्टर 2. निवेश और प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान 3. ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) जगमाल सिंह राठौड़ का निधन 4. 'रंग दे गुलाबी' अभियान 5. ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी थांग-टा प्रतियोगिता में राजस्थान 6. राष्ट्रीय शूटिंगबॉल (महिला-पुरुष) प्रतियोगिता का समापन 7. AVVNL ग्रिड डिजिटाइजेशन हेतु ISA और GEAPP का सहयोग 8. RCA और डेनमार्क क्रिकेट के मध्य क्रिकेट से संबंधित सहयोग
5.	सैक्रिफाइस रेश्यो (Sacrifice Ratio)
6.	अंतर्देशीय जलमार्ग
7.	डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) @2047 रिपोर्ट
8.	भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर
9.	अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)
10.	सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)
11.	सिपरी की वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान, 2025 रिपोर्ट
12.	ग्लोबल नेटवर्क अर्गेंट फूड क्राइसिस



राजस्थान परिदृश्य

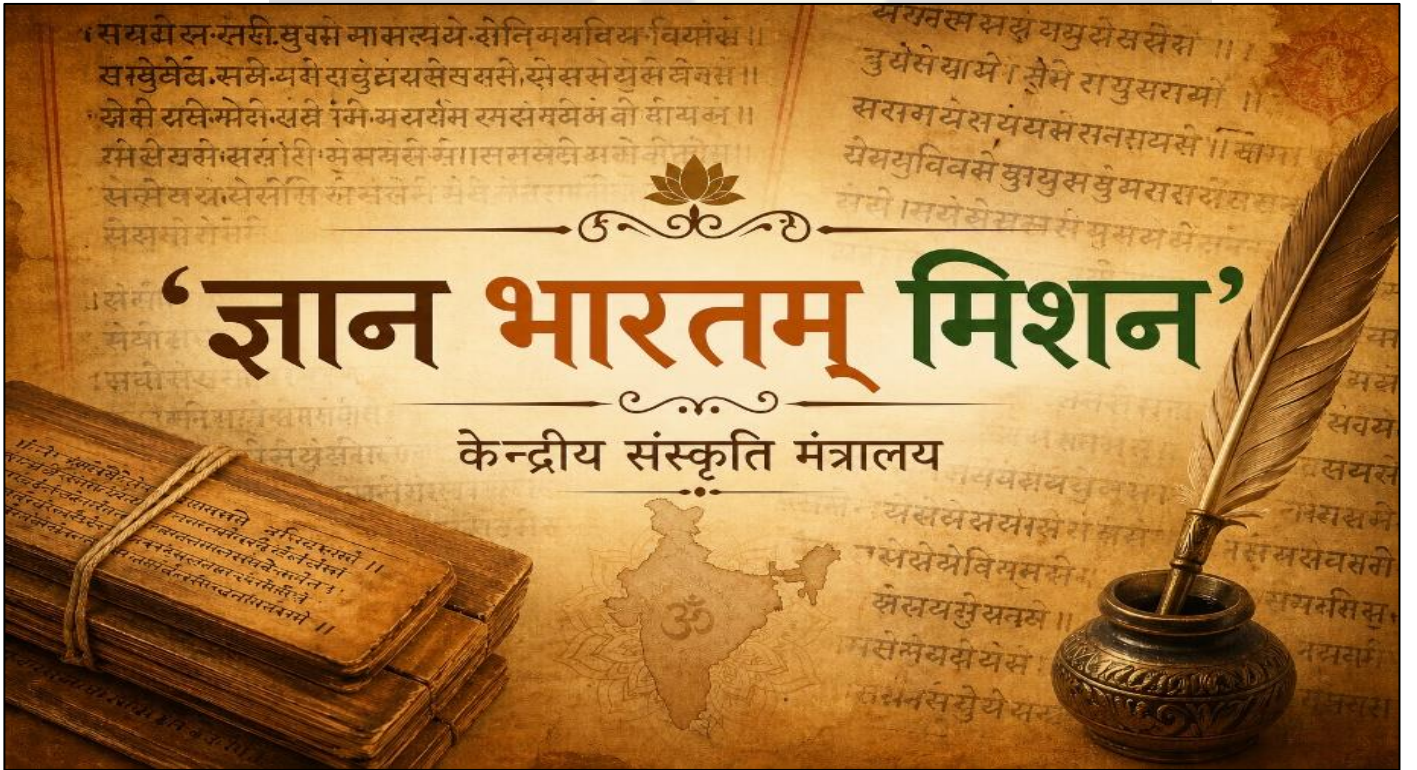


'ज्ञान भारतम् मिशन' के अंतर्गत राज्य के शीर्ष - 3 ज़िले



चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'ज्ञान भारतम् मिशन' के अंतर्गत जयपुर, बीकानेर और जोधपुर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है।



मुख्य बिन्दु:

- जिलेवार पांडुलिपियों की संख्या: जयपुर (4,91,688), बीकानेर (3,39,740) और जोधपुर (1,90,847)।
- ज्ञातव्य है कि 'ज्ञान भारतम् मिशन' के तहत पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण में राजस्थान देशभर में प्रथम स्थान पर है।
- देश की कुल पांडुलिपियों का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में मौजूद है। वर्तमान में राज्य में 13,81,009 पांडुलिपियाँ दर्ज हैं।
- राजस्थान में 16 मार्च, 2026 से प्राचीन ग्रंथों एवं पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत की गई थी।

- राज्यव्यापी सर्वेक्षण के तहत राज्य के पर्यटन, कला-साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन ग्रंथों और पाण्डुलिपियों की खोज और सूचीकरण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।
- **मिशन का लक्ष्य** : दुर्लभ पाण्डुलिपियों का उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल डेटाबेस तैयार करना ताकि उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके।
- **राजस्थान में पाण्डुलिपि सर्वे के लिए नोडल विभाग** : राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर।
- **राजस्थान में पाण्डुलिपि सर्वे के लिए राज्य नोडल अधिकारी** : राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉ. लता श्रीमाली।
- **मुख्य क्लस्टर केंद्र** : राजस्थान में 'ज्ञान भारतम् मिशन' के तहत पाण्डुलिपियों के संरक्षण और उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर को राज्य के मुख्य क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया है।
- **नोट** : बीकानेर स्थित अभय जैन ग्रंथालय को राजस्थान का पहला आधिकारिक पाण्डुलिपि संरक्षण केंद्र घोषित किया गया है।
- **अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:**
- **पाण्डुलिपि (Manuscript)** : वह दस्तावेज़ या ग्रंथ है जिसे हाथ से लिखा गया हो। 'पाण्डुलिपि' शब्द लैटिन के 'मनु' (Manu - हाथ) और 'स्क्रिप्ट' (Script - लिखना) से मिलकर बना है। प्राचीनकाल में प्रिंटिंग प्रेस या कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब ज्ञान और जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए पाण्डुलिपियों का सहारा लिया जाता था। इन्हें अक्सर ताड़ के पत्तों, भोजपत्र, कपड़े, लकड़ी या धातुओं पर लिखा जाता था।
- **फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:**
- **ज्ञान भारतम् मिशन** : केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसकी घोषणा केन्द्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की विशाल हस्तलिखित विरासत (पाण्डुलिपियों) का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है।
- भारत की ज्ञान विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए 11 से 13 सितंबर, 2025 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'पहला ज्ञान भारतम् अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित किया गया।

राजस्थान का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र : ताला (कुंडा की ढाणी)

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अंतर्गत राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर जिले के ताला (कुंडा की ढाणी) में स्थापित किया गया है।



मुख्य बिन्दु:

- 4.9 मेगावाट (MW) क्षमता का यह सौर ऊर्जा संयंत्र 24 बीघा भूमि पर विस्तृत है, जिससे 437 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली सुलभ हो सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना के कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रावधान है।

--:4:--

Daily Current Affairs

Date : 29 April, 2026



- पीएम - कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, जबकि कम्पोनेंट-सी में तीसरे स्थान पर है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (पीएम कुसुम):

- शुरुआत : मार्च, 2019
- पूरा नाम : 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान'।
- नोडल मंत्रालय : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- उद्देश्य : किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों से विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करना।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:5:--

देश का पहला जिंक पार्क - खानखला (भीलवाड़ा)

चर्चा में क्यों?

- राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट - 2024 के अंतर्गत हस्ताक्षरित MoU के तहत भीलवाड़ा के खानखला में एक फ्लैगशिप जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा।



मुख्य बिन्दु:

- इस जिंक पार्क के लिए RIICO द्वारा मास्टर प्लानिंग के साथ-साथ सड़क, जल एवं विद्युत आदि आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएँगी। वहीं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) द्वारा पार्क में अपना प्लांट एवं कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि HZL एवं RIICO के बीच हुई वार्ता में HZL द्वारा खानखला को जिंक पार्क विकसित करने के लिए चिह्नित किया था।

Daily Current Affairs

Date : 29 April, 2026



- खानखला में स्थापित होने वाला यह देश का पहला जिंक पार्क होगा।
- यह जिंक पार्क उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला जिंक पार्क होगा, जिसमें केवल जिंक वेल्यू चेन से संबंधित कंपनियाँ अपना प्लांट लगाएँगी।
- **नोट :** इस पार्क को क्रियाशील बनाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) और त्रिपुरा ग्रुप के बीच भी एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) वेदांता समूह की दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष - 5 चाँदी उत्पादकों में से एक है।
- **स्थापना :** वर्ष 1966 में।
- **मुख्यालय :** उदयपुर (राजस्थान)
- इस कंपनी ने वर्ष 2024 में इकोजेन (EcoZen) लॉन्च किया, जो एशिया का पहला 'लो कार्बन ग्रीन जिंक' ब्रांड है।
- हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वर्ष 2025 में 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स (ICMM)' में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है।

--7--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) का राजस्थान चैप्टर</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में 'इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC)' के राजस्थान चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया।उद्देश्य : इस चैप्टर का मुख्य लक्ष्य राजस्थान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को राज्य स्तर पर मजबूत करना है। यह स्टार्टअप्स और उद्यमियों को वैश्विक बाजार तक पहुँचने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
2.	<p>निवेश और प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान</p> <ul style="list-style-type: none">'इंडिया स्टेट' की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान निवेश और प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में देश का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है।राजस्थान वित्त वर्ष 2025 में निवेश के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 8वें स्थान पर था।निवेश में वृद्धि : एक वर्ष के भीतर राज्य में निवेश लगभग 4 गुना बढ़ा है। यह ₹1.10 लाख करोड़ (FY 2024) से बढ़कर ₹4.65 लाख करोड़ (FY 2025) हो गया है।प्रमुख क्षेत्र : इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा।
3.	<p>ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) जगमाल सिंह राठौड़ का निधन</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, भारत-पाक युद्ध 1971 में अदम्य साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) जगमाल सिंह राठौड़ का बीकानेर में निधन हो गया।ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) जगमाल सिंह राठौड़ का जन्म वर्ष 1938 में बीकानेर जिले के गारबदेसर गाँव में हुआ था।

आर्थिक घटनाक्रम

सैक्रिफाइस रेश्यो (Sacrifice Ratio)

चर्चा में क्यों?

- भारत, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में मुद्रास्फीति नियंत्रण के हालिया उपाय मुद्रास्फीति के प्रबंधन की आर्थिक लागतों को उजागर करते हैं। इन्हें सैक्रिफाइस रेश्यो का उपयोग करके मापा जाता है।

मुख्य बिन्दु:

सैक्रिफाइस रेश्यो

- यह मुद्रास्फीति को कम करने की प्रत्यक्ष आर्थिक लागत को मापता है।
- इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति दर में प्रत्येक 1% की कमी के लिए वास्तविक GDP का कितने प्रतिशत नुकसान होता है।
- यह मापदंड दिखाता है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक संवृद्धि को जारी रखने के बीच एक कठिन संतुलन होता है।
- उच्च अनुपात का अर्थ है कि मुद्रास्फीति से निपटने से महत्वपूर्ण अल्पकालिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनमें बढ़ती बेरोजगारी और औद्योगिक उत्पादन में कमी शामिल हैं।

अंतर्देशीय जलमार्ग



चर्चा में क्यों?

- अंतर्देशीय जलमार्ग संवृद्धि के सक्रिय माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं।



मुख्य बिन्दु:

- अंतर्देशीय जलमार्ग वास्तव में देश के भीतर स्थित ऐसे जलमार्ग होते हैं जो समुद्र का हिस्सा नहीं होते, लेकिन नौवहन यानी जल-परिवहन के लिए उपयोगी होते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग में नदियाँ, नहरें, झीलें, लैगून और ज्वारनदमुख शामिल हैं।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की स्थिति

- **वर्तमान स्थिति:** राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनकी कुल लंबाई 20,187 किलोमीटर है।
- मार्च, 2026 तक, 32 राष्ट्रीय जलमार्ग संचालन में हैं।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में अगले पाँच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को संचालित करने की घोषणा की गई।
- **बढ़ती हिस्सेदारी:** राष्ट्रीय जलमार्गों से माल ढुलाई वित्त वर्ष 2024-25 में 145.84 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई।
- **लक्ष्य:** 'मैरीटाइम अमृत काल विजन' के अनुसार, भारत का लक्ष्य कुल माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 5% करना है।
- साथ ही, अंतर्देशीय जलमार्गों से होकर वर्ष 2030 तक 200 मिलियन मीट्रिक टन और 2047 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलें

- **विधायी पहलें:** भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 लागू किया गया है।

Daily Current Affairs

Date : 29 April, 2026



प्रमुख योजनाएँ:

- **ग्रीन ट्रांजीशन दिशानिर्देश:** इन दिशा-निर्देशों का लक्ष्य 2030 तक अंतर्देशीय जलमार्गों से यात्री परिवहन में कार्बन तीव्रता को 30% तक कम करना है।
- **तटीय कार्गो संवर्धन योजना:** केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इस योजना का उद्देश्य 2047 तक कुल परिवहन में अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत-परिवहन की संयुक्त हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% करना है।

अन्य योजनाएँ:

- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (वाराणसी-हल्दिया खंड) के लिए जलमार्ग विकास परियोजना
- जलवाहक कार्गो संवर्धन योजना, 2024, आदि।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:12:-

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

- ऐतिहासिक भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए गए। यह मुक्त व्यापार समझौता "विकसित भारत 2047" के विजन के अनुरूप है।





मुख्य बिन्दु:

भारत-न्यूजीलैंड FTA के मुख्य बिंदु

- **100% शुल्क-मुक्त पहुँच:** न्यूजीलैंड ने भारत से सभी निर्यातों पर शुल्क समाप्त कर दिया है। इससे MSMEs, वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रकों को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिबद्धता:** न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
- **संवेदनशील क्षेत्रकों का संरक्षण:** भारत ने लगभग 70% वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोलने की अनुमति दी है, जो भारत के साथ न्यूजीलैंड के 95% व्यापार को कवर करता है।
- **लगभग 30% वस्तुओं को इस सूची से बाहर रखा गया है ताकि किसानों और घरेलू उद्योगों की रक्षा हो सके।**
- **रूल्स ऑफ ऑरिजिन का प्रावधान:** द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लाभों के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए उत्पाद विशिष्ट रूल्स ऑफ ऑरिजिन का एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है।
- **रूल्स ऑफ ऑरिजिन वे नियम होते हैं जिनसे यह तय किया जाता है कि कोई उत्पाद मूल रूप से किस देश का है। इन नियमों का महत्त्व इसलिए है क्योंकि कई मामलों में आयात पर लगने वाला शुल्क और प्रतिबंध उसी देश के आधार पर तय होते हैं, जहाँ से वह वस्तु आई है।**
- **प्रतिभा और आवागमन:** STEM के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के अवसर और पढ़ाई के बाद काम करने का वीजा तथा कुशल पेशेवरों को वीजा दिया जाएगा। साथ ही, कुशल भारतीयों के लिए न्यूजीलैंड में हर साल 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा का कोटा तय किया गया है।
- **आयुष का वैश्वीकरण:** पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद और योग को मान्यता दी है, तथा उनके व्यापार को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है।

Daily Current Affairs

Date : 29 April, 2026



- **अन्य प्रावधान:** कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए साझेदारी की जाएगी। साथ ही, 118 सेवा क्षेत्रों में बाजार तक पहुँच मिलेगी और 139 क्षेत्रों में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड संबंध

- **बाजार:** ओशिनिया क्षेत्र में न्यूजीलैंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- **व्यापार:** द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2024-25 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- **भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन:** भारत, न्यूजीलैंड को जितना निर्यात करता है, उससे कम आयात करता है।
- **प्रवासी:** लगभग 300,000 भारतीय प्रवासी न्यूजीलैंड में रहते हैं जो वहाँ की कुल आबादी का लगभग 5% है। ये प्रवासी भारत और न्यूजीलैंड के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु के रूप में कार्य कर रहे हैं।

--:15:--

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)

चर्चा में क्यों?

- वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन से पहले, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस नई दिल्ली घोषणापत्र पर विचार-विमर्श कर रहा है, जिसे यदि अपनाया जाता है, तो यह बिग कैट संरक्षण पर पहला अंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र होगा।

मुख्य बिन्दु:

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)

- इसे भारत द्वारा 2023 में सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा।
- आईबीसीए के अंतर्गत आने वाली सात बड़ी बिल्लियों में से पाँच भारत में पाई जाती हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता।
- यह उन 97 क्षेत्रीय देशों के लिए खुला है जहाँ ये बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं।
- **उद्देश्य:** बड़ी बिल्लियों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए वैश्विक ज्ञान, संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को जुटाना है।






Daily Current Affairs

Date : 29 April, 2026



CIVIL SERVICES

Big Cat Conservation Status

Species	Conservation Status	Key Project(Year)	Unique Feature
 Tiger	Endangered (NTCA)	Project Tiger (1973)	Orange coat with black stripes
 Asiatic Lion	Endangered	Asiatic Lion Reintroduction Project (2004)	Only social big cat; lives in prides
 Leopard	Vulnerable	—	Rosette spots; excellent climber
 Snow Leopard	Vulnerable	Project Snow Leopard (2009)	Long tail for balance; powerful hind legs
 Cheetah	Extinct (reintroduced)	Project Cheetah (2022)	Fastest land animal; solid spots

-:17:-

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) @2047 रिपोर्ट

📢 चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) @2047' रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में DPI 2047 रोडमैप के तहत दो-चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है: DPI 2.0 (2025-2035) और DPI 3.0 (2035-2047)। इस रिपोर्ट में DPI 2.0 पर विस्तृत ध्यान केंद्रित किया गया है।

📌 मुख्य बिन्दु:

DPI 2.0 (रिपोर्ट के मुख्य अंश)

- विस्तार क्षेत्र:** इसमें 8 क्षेत्रों में रूपांतरण का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

DPI 2.0: संरचनात्मक बाधाओं से रूपांतरण तक की पूरी प्रक्रिया



संरचनात्मक बाधाएं

- विश्वास की कमी
- भाषा संबंधी बाधाएं
- अलग-अलग डेटा (साइलो डेटा)
- बाजार तक पहुंच की कमी
- लेन-देन की उच्च लागत
- ज्ञान और क्षमता की कमी

रणनीतिक समाधान	
डेटा का समुचित उपयोग करना	मानव क्षमता बढ़ाना
डिजिटल लेन-देन का विस्तार	AI को सबके लिए सुलभ बनाना



क्षेत्रों का रूपांतरण

लघु उद्योगों के लिए बाजार का विस्तार	MSMEs में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर
लघु भूधारक कृषकों की आजीविका में सुधार	ऊर्जा बाजार का विकेंद्रीकरण
1 अरब से अधिक भारतीयों को ऋण सुविधा	शिक्षा के लिए सुरक्षित डिजिटल परिवेश
सभी के लिए स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं	लाभार्थियों की सही पहचान

MSMEs

कृषि

ऊर्जा

वित्त

शिक्षा

स्वास्थ्य

सामाजिक सुरक्षा

--:18::--

कार्यान्वयन के मुख्य माध्यम:

- **जिला कार्यक्रमों के माध्यम से समग्र माँग:** डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जिला स्तर के विकास लक्ष्यों से जोड़कर स्थानीय समाधान तैयार किए जाएंगे।
- **प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता का विस्तार:** DPI से जुड़े उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **AI में प्रगति का लाभ उठाना:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को सभी के लिए सुलभ बनाया जाएगा।
- **विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक पहलों को लागू करना:** अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसी रणनीतियाँ लागू की जाएंगी, जिससे डेटा का सही उपयोग हो, AI सब तक पहुंचे, लोगों की कौशल क्षमता बढ़े और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिले।

DPI 2.0 के लिए मुख्य सिफारिशें:

- राज्यों के नेतृत्व में विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन हो,
- प्रारंभिक चरण में कृषि तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर ध्यान दिया जाए,
- वैश्विक सहयोग के लिए निष्पक्ष संस्थागत ढाँचा स्थापित किया जाए।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

- **अर्थ:** DPI एक ऐसा डिज़ाइन तरीका है, जिसके जरिए प्रौद्योगिकी और बाजार में नवाचार का उपयोग करके बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक विकास किया जाता है।

DPI के प्रमुख प्रभाव:

- **GDP:** 2022 में भारत की GDP में DPI का योगदान 0.9% था, और 2030 तक इसके 4.2% होने का अनुमान है।
- **नए क्षेत्रों में अवसर के द्वार को खोलना:** GST के तहत पंजीकृत MSMEs की संख्या दिसंबर 2024 में बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई। 2017-18 में यह संख्या 5 लाख थी।
- **वित्तीय समावेशन:** भारत ने केवल 8 वर्षों में 80% लोगों के बैंक खाते खोल दिए, जबकि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार इसमें 47 साल लग सकते थे।
- **हॉकी स्टिक प्रभाव:** ऐसी नई सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ, जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इससे विकास 'हॉकी स्टिक' के आकार की तरह अचानक तेजी से बढ़ने लगा, अर्थात् नई-नई डिजिटल सेवाओं की वजह से विकास अचानक बहुत तेज हो गया।

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के संकलन के लिए एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया है।

मुख्य बिन्दु:

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) विनिर्माण से संबंधित गतिविधियों को दर्ज करता है, लेकिन सेवा क्षेत्रक में अल्पकालिक गतिविधियों को दर्ज करने के लिए कोई सूचकांक नहीं था। इससे समग्र आर्थिक प्रदर्शन के आकलन में डेटा की कमी की समस्या उत्पन्न हो रही थी।

प्रस्तावित सेवा उत्पादन सूचकांक की मुख्य विशेषताएँ

- प्रस्तावित आधार वर्ष: 2024-25
- डेटा स्रोत: वस्तु एवं सेवा कर डेटा, क्षेत्रक आधारित मंत्रालयों से प्रशासनिक डेटा और सेवा क्षेत्रक के निगमित उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण।
- कवरेज: इस सूचकांक को विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्रक की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें थोक और खुदरा व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, संचार आदि उप-क्षेत्रक शामिल हैं।

सिपरी की वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान, 2025 रिपोर्ट



चर्चा में क्यों?

- सिपरी (SIPRI) ने वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान, 2025 रिपोर्ट जारी की है।



मुख्य बिन्दु:

- SIPRI (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) संघर्ष, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध के लिए समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है।
- **स्थापना:** 1966 में स्टॉकहोम (स्वीडन)
- 2025 में सैन्य मद में सबसे अधिक व्यय करने वाले शीर्ष 5 देशों का कुल वैश्विक सैन्य व्यय में 58% हिस्सा रहा। ये देश हैं; संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत।
- 92.1 बिलियन डॉलर के कुल सैन्य व्यय के साथ भारत विश्व में पाँचवाँ सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है।
- पिछले वर्ष की तुलना में भारत के सैन्य व्यय में 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस

चर्चा में क्यों?

- ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट, 2025 जारी की। यह वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट का 10वाँ संस्करण है।

मुख्य बिन्दु:

- रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में 47 देशों के 26.6 करोड़ से अधिक लोगों ने उच्च स्तर की गहन खाद्य असुरक्षा का सामना किया।
- इसका मुख्य कारण संघर्ष है। इससे पहले चरम मौसमी घटनाएँ सबसे बड़ा कारण थीं।

ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस

- **स्थापना:** इसकी स्थापना 2016 में विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी।
- **उद्देश्य:** यह मानवीय और विकास क्षेत्रक में कार्य करने वालों की एक बहु-हितधारक पहल है। इसमें अलग-अलग संगठन खाद्य संकट के मूल कारणों से निपटने और संधारणीय समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के लिए एकजुट हुए हैं।